

प्रसार भारती
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़)
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

18.45 शुक्रवार

दिनांक 20.09.2024

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर वासपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए अगले तीन महीनों में योजना लाएंगे।
 - राज्य सरकार ने पांच विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
 - राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में शहरी विकास नीति को दी गई मंजूरी।
 - प्रदेश के न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री–शिल्पकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनें। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा के स्वावलम्बी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है।

श्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किये। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पचहत्तर हजार लाभार्थियों को डिजिटल ब्रूण स्वीकृति पत्र भी जारी किये।

इधर, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के लाईवलीबुड कॉलेज परिसर में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त चार सौ लाभार्थियों को ई-स्किल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति भगत ने लाभार्थियों को प्रभाण पत्र का वितरण किया।

गृह मंत्री—माओवाद प्रभावित मुलाकात

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए अगले तीन महीनों में योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को चिकित्सा, रोज़गार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने यह बात कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर माओवाद पीड़ितों के एक दल से मुलाकात के दौरान कही। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र के लगभग सत्तर माओवाद पीड़ितों के एक दल ने कल केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की।

इस अवसर पर पीड़ितों ने बताया कि माओवादी हमलों के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान आए हैं। उनमें से कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और कई लोग अपाहिज हो गए हैं। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीड़ितों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार वर्ष दो हजार छब्बीस तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण, वामपंथी उग्रवाद अब छत्तीसगढ़ में बस्तर के कुछ ज़िलों तक ही सीमित होकर रह गया है।

यह दल कल इक्कीस सितंबर को राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगा। इस दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के संबंध में चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष—नियुक्त

राज्य सरकार ने पांच विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्थलगांव की विधायक गोमती साय को सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, कोण्डागांव की विधायक लता उसेण्डी को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह, मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष तथा दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इससे पहले, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से इन पांचों विकास प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत हो गया है। इन प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा सांसद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब इसके सदस्य होंगे। वहीं, आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी इन प्राधिकरणों में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

.....

मंत्रिमंडल—निर्णय

राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में शहरी विकास नीति का अनुमोदन किया गया। यह नीति शहरों के सुव्यवस्थित विकास के साथ ही विकास योजनाओं में प्रस्तावित जन-उपयोगी भूमि का समुचित विकास करने के साथ ही अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत राज्य की शहरी आबादी सुविधाओं का जो अभाव महसूस कर रही है, उन्हें दूर किया जाएगा।

इस नीति के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री—युवा उत्सव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए ना की जॉब सीकर। विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में छह सौ पचास पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति भी दी गई है।

राज्यपाल—स्थापना दिवस समारोह

राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इक्सठवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को गौरव दिलाने के लिए उत्साह के साथ और कड़ी मेहनत करें, जिससे यह देश के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में शामिल हो सके।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का कोई शार्टकट रास्ता नहीं होता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि मातृ भाषा में शिक्षा ग्रहण करने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने रायपुर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा।

समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालय और छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और शिलांग विश्वविद्यालय के बीच टीचर-स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और ट्राइबल बेर्स्ड स्टडीज के लिए एमओयू किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रदेश के न्यायालयों में कल इककीस सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में पारिवारिक मामलों के साथ ही राजस्व, लेन-देन, चेक बाउंस, बिजली बिल, जल कर, सफाई कर और अन्य प्रकरणों का आपसी रजामंदी के साथ निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के न्यायालयों में पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने नागरिकों से अपील की है कि, यदि उनका मामला सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लंबित है तो वे कल इककीस सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त—निर्देश

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों से कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है।

ब्रीफिंग में प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं।

पाठ्य पुस्तक महाप्रबंधक—निलंबित

चालू शैक्षणिक सत्र की नई किताबों को रद्दी में बेचे जाने के मामले में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई चालू सत्र की नई किताबों को रद्दी में बेचे जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बातों—बातों में

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ‘बातों—बातों में’ इस बार राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चुनी गई छत्तीसगढ़ की शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल इककीस सिंतबर को सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

और अब कुछ खबरें संक्षेप में—

- कांकेर में आज से डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कलेकटोरेट परिसर के उप डाकघर में शुरू किए गए इस केन्द्र का शुभारंभ आज सांसद भोजराज नाग ने किया। यह बस्तर संभाग का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र है।
- राज्य के वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियरों सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पीएचई विभाग में एक सौ इक्यासी पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है।

- दुर्ग जिले के रिसाली सेक्टर भिलाई स्थित बी.एस.एफ. के मुख्य कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। इसमें बी.एस.एफ. जवानों द्वारा इक्सठ यूनिट रक्तदान किया गया।
 - केन्द्रीय संचार ब्यूरो द्वारा कल इककीस सितंबर से लेकर तेर्झस सितंबर तक भिलाई—तीन में स्थित मंगलभवन में राष्ट्रीय पोषण माह पर मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।
 - केन्द्रीय जेल दुर्ग में आज एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। इस मामले में ज्यूडिशरी जांच समिति गठित कर दी गई है।
 - सरगुजा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो—एसीबी की टीम ने पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी वीरेन्द्र नाथ पांडेय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी फौती चढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था।